By, Sujeet kr. Suman
R.N. College
(Hajipur)

Q.No-) औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका का वर्णन करें?

उत्तर

"राज्य अब केवल पहरेदार और न्यायाधिकारी मात्र नहीं रह गया है। आज तो राज्य इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि व्यक्ति और समाज का हित बुद्धि और कार्य की सामाजिक प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है और संविधियों के द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। हर दिशा में राज्य का क्षेत्र बढ़ रहा है।"

एक अल्पविकसित देश के औद्योगिक विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य की इस भूमिका को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

(i) प्रबंधन की भूमिका → पूँजीवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अन्तर्गत राज्य निम्नांकित कार्यों का सम्पादन करता है —

(a.) व्यावसायिक कार्यों के प्रारम्भ करने हेतु दशाओं का निर्धारण → राज्य प्रबंधन की भूमिका के अन्तर्गत उन दशाओं या शर्तों को निश्चित करा सकता है जो एक व्यवसाय को शुरू करने के पूर्व अनुमति के रूप में निर्धारित की जा सकती है। इस व्यवस्था को 'शासकीय अनुमति' कहते हैं।

(b.) व्यावसायिक संस्थानों के व्यवहार का निर्धारण → एक व्यावसायिक संस्थान की स्थापना के बाद राज्य यह भी निर्धारित कर सकता है कि अमुक संस्थान किन मापदण्डों या व्यवहार के अन्तर्गत संस्थान चला सकेगा। उदाहरणार्थ, एक संस्थान को निर्धारित करों का भुगतान करना होगा, संस्थान में निर्धारित श्रेणी के माल की व्यवस्था करनी होगी आदि।

(c) अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का नियमन → उपभोक्ता, श्रमिक, विनियोजक आदि अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। राज्य इनके हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रयत्न करता है जैसे- वह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निश्चित कर सकता है, आर्थिक केन्द्रीकरण पर प्रतिबंध लगा सकता है; श्रमिकों के लिए ~~~~ विनियोजकों को उनके हितों की सुरक्षा का मनोनय कर सकता है।

(P.T.O)

राज्य के उपर्युक्त प्रबंधन कार्यों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में विभाजित किया जा सकता है —
प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत — (i) उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करना, (ii) पूँजी के निर्गमन पर नियंत्रण रखना, (iii) विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना, (iv) आयात - निर्यात पर नियंत्रण रखना, (v) उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण रखना, (vi) कम्पनी कानून के अन्तर्गत नियंत्रण रखना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

अप्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत राज्य की वे नीतियाँ सम्मिलित की जाती हैं जो उद्योग एवं व्यापार की सही व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती हैं। राज्य की मौद्रिक, प्रशुल्क व तस्कर नीतियाँ अप्रत्यक्ष कार्यों के ही उदाहरण हैं, उदाहरणार्थ — जब राज्य किसी वस्तु के आयात की ऊँची दरों को प्रोत्साहित करना चाहता है तो वह उन पर कर लगा देता है। इसी प्रकार जब राज्य किसी वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहता है तो कर लगाने में शिथिलता अपनाता है अथवा कर को समाप्त ही कर देता है।

(2.) प्रवर्तक की भूमिका → राज्य को उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में एक प्रवर्तक की भूमिका का निर्वाह भी करना पड़ता है। प्रवर्तक की भूमिका के रूप में संचार सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना, वित्तीय संस्थाएँ स्थापित करना, औद्योगिक शोध व अनुसंधान के लिए सुविधाएँ जुटाना और संस्थाएँ स्थापित करना, प्रबंधकों की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए संस्थान स्थापित करना आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(3.) उद्यमी की भूमिका → आज विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक असंतुलन को समाप्त करने व समाज के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना कर रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में राज्य उद्यमी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(4.) नियोजनकारी भूमिका → अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए नियोजन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं के ये प्रारूप संतुलित व सम्पूर्ण विकास के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किये जाते हैं। इससे उत्पादन व उपभोग में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही बचत और विनियोग को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

— o —

Scanned with CamScanner